



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—बाण 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 334]

नई विल्हेमी, शनिवार, अगस्त 18, 1979/शावाण 27, 1901

No. 334] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 18, 1979/SRAVANA 27, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

मंत्रीमंडल सचिवालय

प्रधिकार

18 अगस्त, 1979

का अन्तर्गत 474(अ).—राष्ट्रपति, मंविधान के अनुच्छेद 77 के
प्रणाली (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार
(कार्य-प्राविन्दन) नियम, 1961 में और संशोधन करते के लिए निम्नलिखित
नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य-प्राविन्दन)
(एक सी एंटीवां मंशोधन) नियम, 1979 है।
(2) ये इनके जासकीय राजपत्र में प्रकाशित होते की तारीख से
प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य-प्राविन्दन) नियम, 1961 (जिन्हें इसके
बाद उक्त नियम कहा जाएगा) की प्रथम अनुसूची के स्थान पर निम्न-
लिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्:—

प्रथम अनुसूची

(नियम 2)

मंत्रालय, विभाग, सचिवालय और कार्यालय

1. कृषि और मिनाई मंत्रालय

(1) कृषि और महकारिता विभाग

(2) खाद्य विभाग

(3) कृषि अनुमंधान और शिक्षा विभाग

(4) मिनाई विभाग

2. वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय।

(1) वाणिज्य विभाग।

(2) नागरिक पूर्ति विभाग।

3. संचार मंत्रालय।

4. रक्षा मंत्रालय।

(मंत्रालय के प्रत्येक रक्षा उन्पादन विभाग और रक्षा पूर्ति
विभाग सहित।)

5. शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय।

(1) शिक्षा विभाग।

(2) समाज कल्याण विभाग।

6. ऊर्जा मंत्रालय।

विद्युत विभाग।

7. विदेश मंत्रालय।

8. वित्त मंत्रालय।

(1) आर्थिक कार्य विभाग।

(2) व्यय विभाग।

(3) राजस्व विभाग।

9. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय।

(1) स्वास्थ्य विभाग।

(2) परिवार कल्याण विभाग।

10. गृह मंत्रालय।

(मंत्रालय के अन्तर्गत राजभाषा विभाग और कार्मिक और¹
प्रणाली सुधार विभाग सहित।)

11. उद्योग मंत्रालय
 (1) श्रीशोभिर विभाग
 (2) भारी उद्योग विभाग

12. सूचना और प्रसारण मंत्रालय

13. शम मंत्रालय

14. विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय
 (1) विधि कार्य विभाग
 (2) विधायी विभाग
 (3) न्याय विभाग
 (4) कम्पनी कार्य विभाग

15. पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्रालय
 (1) पेट्रोलियम विभाग
 (2) रसायन और उर्वरक विभाग

16. योजना मंत्रालय, मांशिकी विभाग सहित

17. रेल मंत्रालय, रेल बोर्ड

18. ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय

19. नौकरी और परिवहन मंत्रालय

20. इस्पात, आन और कोयला मंत्रालय
 (1) इस्पात विभाग
 (2) आन विभाग
 (3) कोयला विभाग

21. पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय
 (1) पुनर्वास विभाग
 (2) पूर्ति विभाग

22. पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

23. निर्माण और श्रावास मंत्रालय

24. परमाणु कर्ज विभाग

25. संस्कृति विभाग

26. इलेक्ट्रानिकी विभाग

27. संसदीय कार्य विभाग

28. विद्यान और प्रौद्योगिकी विभाग

29. भ्रंशरिक विभाग

30. भवित्वमंडल संविधालय

31. राष्ट्रपति सचिवालय

32. प्रधान मंत्री कार्यालय

33. योजना आयोग ।

3. उक्त नियमों के त्रितीय अनुसूची में—
 (क) “हृषि और भिचाई मंत्रालय” शीर्षक के अन्तर्गत, “क. हृषि विभाग” उपर्योक्त और उसके अन्तर्गत प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उप-शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, प्रथमतः—

“क. हृषि और सद्कारिता विभाग

भाग—I

निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची I के अन्तर्गत हैः—

- प्रस्तराष्ट्रीय कृषि संगठनों, जैसे संयुक्त ग्राष्ट के स्वाधी श्रीशोभिर विभाग संगठन के माथ समाई, कोप्रापरेटिव फार अमेरिकन इंजीक प्रूर्वावृत्ति (मी० ए० आर० फ०) के कृषि आदि संबंधित माल का प्रबंध करना।
- कृषि में संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संगमों तथा अन्य निकायों में भाग लेना और वहां पर किए गये विनिश्चयों का कार्यान्वयन।
- टिहू नियंत्रण का अभिसमय।
- बनस्पति निरोध।
- वे उद्योग, जिनके लिए संमद ने विधि द्वारा धोषणा की है कि उन पर संथ का नियंत्रण लोकहित में समीक्षीय है, वहां तक जहां तक वे निम्नलिखित से सम्बद्ध हैं—
 (क) कुछ कृषि उत्पादों (दुध, चूप, शिशु दुध आहार, मालूद मिश्रित दुध आहार, संधित दुध, भी और अन्य डेरी उत्पाद), मास और मास उत्पादों का संसाधन और प्रणीतन;
 (ख) हृषि उद्योगों (मणीनरी, उर्वरक, बीज और पशु जाथ सहित) का इस परिवेश के माथ विकास कि कृषि उद्योगों (मणीनरी और उर्वरक सहित) के विकास के बारे में कृषि विभाग के हृत्य भागों के आकलन और लक्ष्यों के नियन्त्रण से अधिक न हों;
 (ग) ग्रास्क लाल उद्योग;
 (घ) मछलियों का संसाधन (जिसके अन्तर्गत तिन्हों में बन्द करना और हिमीकरण भी सम्मिलित है);
 (ङ) मरस्य संसाधन उद्योग के लिए विकास परिषद् की स्थापना और उसकी प्रबंध-व्यवस्था; और
 (च) मरस्य संसाधन उद्योगों की तकनीकी सहायता और सलाह।
- अन्तर्राष्ट्रीय और समूही पकड़ना और मीनधेन।
- राज्यक्षेत्रीय समुद्र से परे मछली पकड़ना और मीनधेन (जिसके अन्तर्गत गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का स्थेन, बम्बई है)।
- मीलिक गवेषणा, जिसके अन्तर्गत उसका समत्वय और बन विज्ञान में उच्चतर गिराव है।
- कृषि संबंधी गणना और पण्डित गणना।
- प्रवित भारतीय सेशन्य—भारतीय हृषिसेवा, भारतीय बन सेवा।
- ग्राम विकास स्कीम।
- प्राकृतिक विपत्तियों के कारण फसलों को हुए तुकसान और पशुधन को हुई हानि संबंधी मामले।
- महामारियों से भिन्न, प्राकृतिक विपत्तियों द्वारा भावयक हुए राहत उपायों का समत्वय।
- महामारियों से भिन्न, सभी प्राकृतिक विपत्तियों के कारण मानव जीवन और सम्पत्ति को होने वाली हानि से संबंधित मामले।
- भारतीय जन दुष्प्रभावन्यास।

भाग—II

निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सक्तम अनुसूची की सूची III के अन्तर्गत हैं, (केवल विधान की भाबत) :—

16. याद्य पदार्थों से भिन्न कृषि उत्पादों में अपमिश्रण ।
17. भार्यिक योजना (कृषि प्रर्थनास्त्र और सांस्कृतिक) ।
18. वृत्तियां (पशु चिकित्सा व्यवसाय) ।
19. पशुओं या बनस्पति को हानि पहुंचाने वाले संकामक या सांस्कृतिक रोगों या नाशकीयों के, जिनके अन्तर्गत टेंटुओं भी हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में फैलने का निवारण ।
20. आषाढ़, शर्करा, बनस्पति, तिलहनों, बनस्पति तेलों, खेती और धना, पटमन, रुई और चाय के निवाय, कृषि वस्तुओं की कीमत का नियन्त्रण ।
21. तिलहनों का उत्पादन ।
22. भूमि अर्जन प्रधिनियम, 1894 का प्रशासन और संघ के प्रयोजनों के लिए भूमि अर्जन सम्बन्धी अन्य मामले ।
23. किसी राज्य में उस राज्य से बाहर पैदा हुए कर-विषयक दावों तथा अन्य सार्वजनिक अभियाचनाओं की, जिनके अन्तर्गत भू-राजस्व बकाया और इस प्रकार बसूल की जाने थाली बकाया रहा है, बसूली ।
24. स्वयं अपने अधिकरणों द्वारा या सहकारी संघों द्वारा ढेरी विकास स्कीमों का भार प्रपने ऊपर लेने वाले विभिन्न राज्यों द्वारा विशेष सहायता का रूप ।
25. बाहु अभियान I और II, तथा उनसे सम्बद्ध सभी मामले ।
26. पशुओं के प्रति नियन्त्रण का निवारण ।

भाग—III

संघ राज्यक्षेत्रों के लिए उपर्युक्त भाग I और II में वर्णित विषय जहाँ तक वे इन राज्यक्षेत्रों की भाबत विद्यमान हैं, और इनके अतिरिक्त निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सक्तम अनुसूची की सूची II के अन्तर्गत हैं :—

27. कृषि (कृषि शिक्षा और गवेषणा से भिन्न), मारकों से रक्षा और पादप रोगों का निवारण ।
28. भूमि, भ्रातृति भाटक का नियन्त्रण, कृषि भूमि का हस्तान्तरण और अन्य संकामण, भूमि सुधार और कृषि सम्बन्धी उधार, जिनके अन्तर्गत नियमित और सगर यांत्रिक गुप्तारों के लिए कृषि भूमि से भिन्न भूमि का अर्जन नहीं है ।
29. भू-गजन्य, जिसके अन्तर्गत राजस्व का निवारण और संप्रहण, राजस्व प्रयोजनों के लिए परिमाप और राजस्व का अन्य संकामण भी है ।
30. पशु नस्ल का परिरक्षण, संरक्षण और उत्पत्ति और पशु-रोगों का निवारण; शालिहांसी प्रणिक्षण और व्यवसाय ।
31. बन, बन-नीति, जिसके अन्तर्गत बन जन्तुओं का परिरक्षण है, और जहाँ तक गण्डभान और निकांदार द्वीपों का सम्बन्ध है वहाँ और बन-प्रशासन से सम्बद्ध सभी मामले ।
32. प्रसिपालक अधिकरण ।
33. कृषि भूमि के उत्तराधिकार के विषय में गूल्क ।
34. कृषि क्षेत्र में सहयोग, कृषि ऋण और ऋणप्रस्तता ।
35. कृषि उत्पाद के विषयत राम्बन्धी सामान्य नीति जिम्में कीमत-निवारण, निर्यात आदि सम्मिलित हैं ।

36. शीमा (फुराल और पशु शीमा) ।

37. सभी सैक्टरों में गहकारिता और सहकारी क्रियाकलापों के सम्बन्ध के क्षेत्र में साधारण नीति (गम्बन्धित मंत्रालय अपने अपने क्षेत्रों में गहकारी संस्थाओं के लिए उत्तरदायी है) ।

38. गाढ़ीय सहकारी संगठनों से गम्बन्धित मामले ।

39. गाढ़ीय सहकारी त्रिकाग निगम ।

40. ऐसी गहकारी सौमाइटियों का, जिनके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं है, नियमन, विनियमन और परिमापन ।

41. गहकारी विभागों और सहकारी संस्थाओं के कार्मिकों का प्रशिक्षण (जिसमें सदस्यों, पदाधिकारियों और गैर-गरकारी अधिकारियों की शिक्षा सम्मिलित है) ।

भाग—IV

साधारण और पारिणामिक :—

42. जहाँ तक कृषि और सम्बद्ध विषयों का सम्बन्ध है यहाँ तक विवेशों और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त विवेशी सहायता से सम्बद्ध मध्य मामले, जिनके अन्तर्गत वे सभी मामले हैं, जो हृषि और सम्बद्ध विषयों के क्षेत्र में भारत द्वारा विवेशों को दी गई सहायता से सम्बद्ध हैं, किन्तु जिनके अन्तर्गत कृषि गवेषणा और शिक्षा तथा सहबद्ध विषयों के क्षेत्र में के ऐसे मामले नहीं हैं जो कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग को विनियिष्ट समनुविष्ट किये गये हैं ।

43. कृषि और उत्पादन कृषि, जिनके अन्तर्गत (क) कृषि प्रयोजनों के लिए गिवाई (ख) लघु और आपातकालीन गिवाई संकर्म, जिनके अन्तर्गत नलकूप हैं, (ग) भूमिगत जल घोज है ।

44. बायो एम्बेटिक योजना ।

45. पशु-पालन, जिसके अन्तर्गत (क) कांडी हाउस और पशु अतिकार, (ख) लघु पशियों और जीव-जन्तुओं का संरक्षण (ग) होरों का उपयोग और वध है ।

46. कृषि उत्पादन—प्रधिक प्रश्न और चारा उपजाओ ।

47. भूमि उद्धार ।

48. रुई और पटमन का विकाग ।

49. विकास कार्यक्रमों में सम्बद्ध मुद्रा भवेक्षण ।

50. गजन्य भू-संरक्षण और वन विकाग स्कीमों को विस्तीर्ण सहायता ।

51. उर्वरक और खात्र (मांगों का प्रत्यक्षन, लक्ष्यों का नियन्त्रण और उर्वरकों का वितरण) ।

52. (क) उर्वरक (नियन्त्रण) आदेश, 1957 और (ख) उर्वरक (संत्रनन नियन्त्रण) आदेश, 1960 का प्रशासन ।

53. कोटाशी अधिनियम, 1968 का प्रशासन ।

54. कृषि उपकरण और मशीनरी ।

55. देश में विद्यार्थी शिक्षा और प्रशिक्षण का संगठन और विकास ।

56. संधन कृषि जिला कार्यक्रम ।

57. संधन कृषि क्षेत्र ।

58. फसल अभियान, फसल प्रतियोगताएं और कृषक संगठन ।

59. भूमिहांसा कृषि श्रमिकों को बयाने के लिए राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त स्कॉर्स ।

60. गांविक कार्म ।

61. इन सूची में विनियिष्ट विषयों में से किसी से गम्बन्धित सभी संघर्ष और अधीनस्थ कार्यक्रम अथवा अन्य संगठन ।

62. ऐसी परियोजनाओं के बिषय, जो किसी अन्य विभाग को विनिर्दिष्ट: आवंटित हैं। इन सूची में शम्मिलित किए गए विषयों के अन्तर्गत आने वाली पंक्ति सैकटर परियोजनाएँ।

63. इस विभाग को आवंटित विषयों में से किसी से गम्भीर विषयों के बिन्दु अपराध।

64. इस विभाग को आवंटित विषयों में से किसी के प्रयोजनों के लिये जात्र और सांख्यिकी।

65. इह विभाग को आवंटित विषयों में से किसी की बाबत फीसे उन फीसों के निवाय जो न्यायालय में ली जाती है।

(ख) "बाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय" शीर्षक के स्थान पर "बाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय" शीर्षक रखा जाएगा, और इग प्रकार प्रतिस्थापित शीर्षक के अन्तर्गत, "क. धाणिज्य विभाग" उप-शीर्षक और उनके अन्तर्गत आने वाली प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित उप-शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"ख नागरिक पूर्ति विभाग

I—शान्तरिक व्यापार

- आन्तरिक व्यापार।
- अन्तर्राजियक व्यापार, स्पिरिट्यूक्स निर्मिति (अन्तर्राजियक व्यापार और बाणिज्य) नियंत्रण अधिनियम, 1955।
- वायवा याजार का नियंत्रण [अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952]।
- आवश्यक वस्तु प्रधिनियम, 1955 (ऐसी आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय, कीमतें और वितरण, जो विनिर्दिष्ट: किसी अन्य मंत्रालय द्वारा अवशूल नहीं हैं)।
- उपभोक्ता सहकारी संस्थाएँ।
- लोक वितरण प्रणाली।
- कीमतों का परिवर्कण और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता।
- राष्ट्रीय उपभोक्ता सरक्षण परियद्।
- पैक की हुई वस्तुओं का विनियमन।
- कानूनी माप-विद्या में प्रशिक्षण।
- वे अद्योग, जिनके लिए संसद ने विधि द्वारा घोषणा की है कि उन पर संघ का नियंत्रण लोकहित में समीक्षीय है, जहाँ तक ये घनस्पति थी, निःहत, बनस्पति तेलों, खर्ले और बगा से मध्यदूर हैं।
- बनस्पति थी, तिलहन, बनस्पति तेलों, खर्ली और बगा का अन्तर्राजियक व्यापार और बाणिज्य, उनका मूल्य नियंत्रण पूर्ति और वितरण।
- बनस्पति थी, बनस्पति तेल और बगा निवेशालय।

II—व्यापार चिन्ह आदि

- व्यापार और बाणिज्य चिन्ह अधिनियम, 1958।
- संप्रतीक और नाम (घनुचित प्रयोग का निवारण) अधिनियम, 1950।
- बाट और माप मानक (बाट और माप मानक अधिनियम, 1956—बाट और माप मानक अधिनियम, 1976)।
- भारतीय भानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) अधिनियम, 1952।

18. इन सूची में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय से गम्भीर विषय या अधीनस्थ कार्यालय या अन्य संगठन, जिसमें फारव और मार्केट मन्त्रालय, अम्बाई भी शम्मिल है।

(ग) "उद्योग मंत्रालय" शीर्षक के अन्तर्गत, "क. श्रीलोकिक विकास विभाग" उप-शीर्षक के नीचे, मध्य "VII आगांश्चोग" और उनके अन्तर्गत 36 और 37 प्रविष्टियों का लाप किया जाएगा।

(घ) "रेल मंत्रालय, रेल बोर्ड" शीर्षक और उनके अन्तर्गत आने वाले प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियों रखी जाएंगी, अधित्:—

"ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय

- पंचायती राज से गम्भीर विषय रामें सामर्थ्य।
- भूमि भूधार, भूमि-धारण भूधिकार, भूमि-वेकार, जोहों की बाबत नियंत्रण गम्भीर विषय।
- ग्रामीण क्षेत्रों में मंशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम से गम्भीर विषय।
- (क) ग्राम जल पूर्ति और ग्राम मधुकों की सीधी जिम्मेदारी;
- (ख) प्राथमिक शिक्षा, प्रीड शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्राम विद्युतीकरण, भूमिकीन ग्रामीण अधिकारों के लिए आवास और पोषण नायंक्रम का तोड़न दर्शिन्व।
- ग्रामीण बेरोजगारी का सुकाबला करने के लिए कार्यक्रम जिनमें 'काम के लिए अनाज' कार्यक्रम, प्रणिक्षण कार्यक्रम और ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम सम्मिलित हैं।
- भवींगीण ग्रामीण विकास जिसमें लघु कृषक विकास अभिकरण, मोमाल लघुकृषक और कृषि मशहूर, सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम आदि शम्मिलित हैं।
- गहड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मछल्यव विकास कार्यक्रम और आदिवासी क्षेत्र विकास कार्यक्रम।
- ग्राम एवं कुटीर उद्योग।
- जन सहयोग, जिसमें ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए स्वयंसेवी प्रभिकरणों से गम्भीर सभी विषय सम्मिलित हैं।
- ग्रामीण क्षेत्रों में भवित्व व्यवस्था विषय में ग्रामीण गोवान ग्रामों में है।
- नगर और ग्राम योजना, जहाँ तक इसका गम्भीर ग्रामीण क्षेत्रों से है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मंडियों की स्थापना और कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937।
- इस सूची की मर्दों से सम्बन्धनीय सहकारी समितियाँ।
- इस सूची में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय से गम्भीर विषय उद्योग अधीनस्थ कार्यालय तथा अन्य संगठन।

(इ) "निर्माण और आवास मंत्रालय" शीर्षक के अन्तर्गत, 23-ड प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"23-ड. पैय जलपूर्ति, ग्रामीण जल पूर्ति को छोड़कर, और स्वच्छता।"

(नीलम संगीव रेडी)
राष्ट्रपति

[मं. 74/2/3/79-मंत्रिता]
के० महाराष्ट्र, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th August, 1979

S.O. 474(E)—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Governments of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and thirty-fifth Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, (hereinafter referred to as the said rules) for the First Schedule, the following schedule shall be substituted, namely :—

“THE FIRST SCHEDULE
(Rule 2)

MINISTRIES, DEPARTMENTS, SECRETARIATS AND OFFICES (MANTRALAYA, VIBHAG, SACHIVALAYA TATHA KARYALAYA)

1. Ministry of Agriculture and Irrigation (Krishi aur Sinchay Mantralaya) :

- (i) Department of Agriculture and Co-operation (Krishi aur Sahakarita Vibhag).
- (ii) Department of Food (Khadya Vibhag).
- (iii) Department of Agricultural Research and Education (Krishi Anusandhan aur Shiksha Vibhag).
- (iv) Department of Irrigation (Sinchay Vibhag).

2. Ministry of Commerce and Civil Supplies (Vanijya aur Nagrik Poorti Mantralaya) :

- (i) Department of Commerce (Vanijya Vibhag).
- (ii) Department of Civil Supplies (Nagrik Poorti Vibhag).

3. Ministry of Communications (Sanchay Mantralaya).

4. Ministry of Defence (Raksha Mantralaya) :

[with a Department of Defence Production (Raksha Utpadan Vibhag) and a Department of Defence Supplies (Raksha Poorti Vibhag) within the Ministry (Mantralaya)].

5. Ministry of Education and Social Welfare (Shiksha aur Samaj Kalyan Mantralaya) :

- (i) Department of Education (Shiksha Vibhag).
- (ii) Department of Social Welfare (Samaj Kalyan Vibhag).

6. Ministry of Energy (Oorja Mantralaya) Department of Power (Vidyut Vibhag).

7. Ministry of External Affairs (Videsh Mantralaya).

8. Ministry of Finance (Vitta Mantralaya) :

- (i) Department of Economic Affairs (Arthik Karya Vibhag).
- (ii) Department of Expenditure (Viyaya Vibhag).
- (iii) Department of Revenue (Rajuswa Vibhag).

9. Ministry of Health and Family Welfare (Swasthya aur Parivar Kalyan Mantralaya) :

- (i) Department of Health (Swasthya Vibhag).
- (ii) Department of Family Welfare (Parivar Kalyan Vibhag).

10. Ministry of Home Affairs (Grih Mantralaya) :

[With a Department of Official Language (Rajbhasha Vibhag) and a Department of Personnel and Administrative Reforms (Karmik aur Prashasanik Sudhar Vibhag) within the Ministry (Mantralaya)].

11. Ministry of Industry (Udyog Mantralaya) :

- (i) Department of Industrial Development (Audyogik Vikas Vibhag).
- (ii) Department of Heavy Industry (Bhari Udyog Vibhag).

12. Ministry of Information and Broadcasting (Soochana aur Prasaran Mantralaya).

13. Ministry of Labour (Shram Mantralaya).

14. Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Vidhi, Nyaya aur Kampani Karya Mantralaya) :

- (i) Department of Legal Affairs (Vidhi Karya Vibhag).
- (ii) Legislative Department (Vidhaye Vibhag).
- (iii) Department of Justice (Nyaya Vibhag).
- (iv) Department of Company Affairs (Kampani Karya Vibhag).

15. Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Petroleum, Rasayan aur Urvarak Mantralaya) :

- (i) Department of Petroleum (Petroleum Vibhag).
- (ii) Department of Chemicals and Fertilizers (Rasayan aur Urvarak Vibhag).

16. Ministry of Planning (Yojana Mantralaya) with a Department of Statistics (Sankhyiki Vibhag).

17. Ministry of Railways (Rail Mantralaya) Railway Board.

18. Ministry of Rural Reconstruction (Gramin Punarnirman Mantralaya).

19. Ministry of Shipping and Transport (Nauvahan aur Pariwahan Mantralaya).

20. Ministry of Steel, Mines and Coal (Ispat, Khan aur Koyala Mantralaya) :

- (i) Department of Steel (Ispat Vibhag).
- (ii) Department of Mines (Khan Vibhag).
- (iii) Department of Coal (Koyala Vibhag).

21. Ministry of Supply and Rehabilitation (Poorti aur Punarwas Mantralaya) :

- (i) Department of Rehabilitation (Punarwas Vibhag).
- (ii) Department of Supply (Poorti Vibhag).

22. Ministry of Tourism and Civil Aviation (Paryatan aur Nagar Vimanan Mantralaya).

23. Ministry of Works and Housing (Nirman aur Awas Mantralaya).

24. Department of Atomic Energy (Parmanu Oorja Vibhag).

25. Department of Culture (Sanskriti Vibhag).

26. Department of Electronics (Electronics Vibhag).

27. Department of Parliamentary Affairs (Sansadiya Karya Vibhag).

28. Department of Science and Technology (Vigyan aur Pradyogiki Vibhag).

29. Department of Space (Antareeksh Vibhag).

30. Cabinet Secretariat (Mantrimandal Sachivalaya).

31. President's Secretariat (Rashtrapati Sachivalaya).

32. Prime Minister's Office (Pradhan Mantri Karyalaya).

33. Planning Commission (Yojana Ayog).

3. In the Second Schedule to the said rules—

- (a) under the heading “MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (KRISHI AUR SINCHAY MANTRALAYA)” for the sub-heading “A. DEPARTMENT OF AGRICULTURE (KRISHI VIBHAG)”, and the entries thereunder, the following sub-heading and entries shall be substituted, namely :—

A. DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION (KRISHI AUR SAHKARITA VIBHAG)

PART I

The following subjects which fall within List I of the Seventh Schedule to the Constitution of India :—

1. Liaison with International Agri-organisations like Food and Agriculture Organisation of the United Nations, handling of CARE goods concerning agriculture etc.

2. Participation in international conferences, associations and other bodies concerning agriculture and implementation of decisions made thereat.

3. Convention on Locust Control.

4. Plant Quarantine.

5. Industries, the control of which by the union is declared by Parliament by Law to be expedient in public interest, as far as these relate to :—

(a) Processing and refrigeration of certain agricultural products (milk powder, Infant milk food, Malted milk food, Condensed milk, Ghee and other dairy products), Meat and meat products;

(b) Development of Agricultural industries including machinery, fertilizer, seeds and cattle-feed with the limitation that in regard to the development of agricultural industries including machinery and fertilizer, the functions of the Department of Agriculture (Krishi Vibhag) do not go further than the formulation of demands and the fixation of targets;

(c) Shellac Industry;

(d) Processing of fish (including canning and freezing);

(e) Establishment and servicing of Development Council for fish processing industry ; and

(f) Technical assistance and advice to fish processing industry.

6. Fishing and fisheries inland and marine.

7. Fishing and fisheries beyond territorial waters (including Deep-Sea Fishing Station, Bombay).

8. Fundamental research including co-ordination, thereto and higher education in Forestry.

9. Agricultural and Livestock Census.

10. All India Services-Indian Agricultural Service ; Indian Forest Service.

11. Sugarcane development scheme.

12. Matters relating to damage to crops and loss of livestock due to natural calamities.

13. Co-ordination of relief measures necessitated by natural calamities, other than epidemics.

14. Matters relating to loss of human life and property due to all natural calamities, other than epidemics.

15. Indian Peoples' Famine Trust.

PART II

The following subjects which fall within List III of the Seventh Schedule to the Constitution of India (as regards Legislation only) :—

16. Adulteration of agricultural products other than foodstuffs.

17. Economic Planning (Agricultural Economics & Statistics).

18. Professions (Veterinary Practice).

19. Prevention of the extension from one State to another of infectious or contagious diseases or pests affecting animals or plants including locusts.

20. Price control of agricultural commodities except foodgrains, sugar, vanaspati, oil seeds, vegetable oils, cakes and fats, Jute, Cotton and Tea.

21. Production of oil Seeds.

22. Administration of Land Acquisition Act, 1894, and other matters relating to acquisition of land for the purposes of the Union.

23. Recovery of claims in a State in respect of taxes and other public demands, including arrears of land revenue and sums recoverable as such arrears, arising outside that State.

24. Pattern of financial assistance to various State undertaking Dairy Development Schemes either through their own agencies or through the Co-operative Unions.

25. Operation Flood I and II, and all matters pertaining thereto.

26. Prevention of Cruelty to Animals.

PART III

For the Union Territories the subjects mentioned in Parts I and II above, so far as they exist in regard to these Territories and in addition to following subjects which fall within List II of the **Seventh Schedule to the Constitution of India** :—

27. Agriculture (other than agricultural education and research), protection against pests and prevention of plant diseases.

28. Land, that is to say collection of rents, transfer and alienation of land and improvement and agricultural loans, excluding acquisition of non-agricultural land or buildings, town planning improvements.

29. Land revenues, including the assessment and collection of revenue, survey for revenue purposes, alienation of revenues.

30. Preservation, protection and improvement of stocks and prevention of animal diseases ; veterinary training and practice.

31. Forests—Forest Policy including wild life, preservation; and all matters relating to forests and forest administration in so far as Andaman and Nicobar Islands are concerned.

32. Courts of Wards.

33. Duties in respect of succession to agricultural land.

34. Co-operation in agricultural sector, agricultural credit and indebtedness.

35. General Policy relating to the marketing of agricultural produce including pricing, exports etc.

36. Insurance (Crop and Cattle Insurance).

37. General policy in the field of Co-operation and Co-ordination of co-operation activities in all sectors (The Ministries concerned are responsible for Co-operatives in the respective fields).

38. Matters relating to National Co-operative Organisation.

39. National Co-operative Development Corporation.

40. Incorporation, regulation and winding up of co-operative societies with objects not confined to one State.

41. Training of personnel of co-operative departments and co-operative institutions (including education of members, office bearers and non-officials).

PART IV

General and Consequential—

42. All matters relating to foreign aid received from foreign countries and international organisations in so far as agricultural and allied subjects are concerned, including all matters relating to assistance afforded by India to foreign countries in the field of agriculture and allied subjects but excluding such matters in the field of agricultural research and education and allied subjects as are specifically assigned to the Department of Agricultural Research and Education (Krishi Anusandhan aur Shiksha Vibhag).

43. Agriculture and horticulture including (a) Irrigation for agricultural purposes, (b) Minor and emergency irrigation works including tube wells (c) Ground Water Exploration.

44. Bio-aesthetic Planning.

45. Animal Husbandry including—(a) ponds and cattle trespass ; (b) protection of wild birds and animals ; (c) cattle utilisation and slaughter.

46. Agricultural Production—Grow more food and fodder.

47. Land Reclamation.

48. Development of Cotton and Jute.

49. Soil Survey in connection with development programmes.

50. Financial assistance to State Soil Conservation and Forestry Development Schemes.

51. Fertilisers and Manures (Formulation of Demands, fixation of targets and distribution of fertilisers).

52. Administration of (a) Fertiliser (Control) Order, 1957, (b) Fertiliser (Movement Control) Order, 1960.

53. Administration of Insecticides Act, 1968.

54. Agricultural Implements and Machinery.

55. Organisation and development of Extension education and training in the country.

56. Intensive Agricultural District Programme.

57. Intensive Agricultural Areas.

58. Crop campaigns, crop competitions and farmers organisations.

59. Schemes received from States and Union Territories for the settlement of Landless agricultural Labourers.

60. Mechanised Farms.

61. All Attached and Subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.

62. Public Sector Projects falling under the subjects in this list except such projects as are specifically allotted to any other Department.

63. Offences against laws with respect to any of the subjects allotted to this Department.

64. Inquiries and statistics for the purposes of any of the subjects allotted to this Department.

65. Fees in respect of any of the subjects allotted to this Department except fees taken in a court.;

(b) for the heading "MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (VANIJYA, NAGRIK POORTI AUR SAHKARITA MANTRALAYA)", the heading "MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES (VANIJYA AUR NAGRIK POORTI MANTRALAYA)" shall be substituted, and under the heading as so substituted, after the sub-heading "A. DEPARTMENT OF COMMERCE (VANIJYA VIBHAG)", and the entries thereunder, the following sub-heading and entries shall be substituted, namely:—

"B. DEPARTMENT OF CIVIL SUPPLIES (NAGRIK POORTI VIBHAG)

I. Internal Trade

1. Internal Trade.

2. Inter-State trade; the Spirituous Preparations (Inter-State Trade and Commerce) Control Act, 1955.

3. Control of futures trading [The Forward Contracts (Regulation) Act, 1952].

4. The Essential Commodities Act, 1955 (Supply, prices and distribution of essential commodities not dealt with specifically by any other Ministry).

5. Consumer Cooperatives.

6. Public Distribution System.

7. Monitoring of prices and availability of essential commodities.

8. The National Consumer Protection Council

9. Regulation of packaged Commodities.

10. Training in legal Metrology.

11. Industries, the control of which by the Union is declared by Parliament by law to be expedient in public interest, as far as these relate to Vanaspati, Oil seeds, Vegetable Oils, Cakes and Fats.

12. Price control of and inter-state trade and commerce in and supply and distribution of Vanaspati, Oil seeds, Vegetable Oils, Cakes, and Fats.

13. Directorate of Vanaspati, Vegetable Oils and Fats.

II. Trade Marks etc.

14. The Trade and Merchandise Marks Act, 1958.

15. The Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950.

16. Standards of weights and Measures (The Standards of Weights and Measures Act, 1956—The Standards of Weights and Measures Act, 1976).

17. The Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952.

18. All attached or subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list, including the Forward Markets Commission, Bombay.;

(c) under the heading "MINISTRY OF INDUSTRY (UDYOG MANTRALAYA)" under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (AUDYOGIK VIKAS VIBHAG)", item "VII. Village Industries" and entries 36 and 37 thereunder shall be omitted.

(d) after the heading "MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA) (RAILWAY BOARD)" and the entries thereunder, the following heading and entries be inserted namely :—

"MINISTRY OF RURAL RECONSTRUCTION (GRAMIN PUNARNIRMAN MANTRALAYA)

1. All matters relating to Panchayati Raj.

2. Land reforms, land tenures, land records, consolidation of holdings and other related matters.

3. All matters relating to the revised minimum needs programme in the rural areas as below :—

(a) direct responsibility for rural water supply and rural roads ;

(b) nodal responsibility for elementary education, adult education, rural health, rural electrification, housing for landless rural labour and the nutrition programme.

4. Programmes for tackling rural unemployment including 'food for work' programme training programmes and rural works programmes.

5. Integrated rural development, including small farmers development agency, marginal farmers and agricultural labourers, drought prone area programmes, etc.

6. Hill areas development programme, desert development programmes and tribal areas development programmes.

7. Village and cottage industries.

8. Public cooperation, including all matters relating to voluntary agencies for rural reconstruction.

9. Warehousing in rural areas, including rural godowns.
10. Town and country planning, so far as it relates to rural areas.
11. Setting up of agricultural markets in rural areas and the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937.
12. Cooperatives relatable to the items in this list.
13. All attached or subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.”,

(e) under the heading “MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (NIRMAN AUR AWAS MANIRALAYA)”, for entry 23E., the following entry shall be substituted, namely :—

“23E. Drinking water-supply, excluding rural water supply, and sanitation.”

N. SANJIVA REDDY President

[No. 74/2/3/79-Cab.]

K. SAIGAL, Joint Secretary